[श्री अनन्तराम देवशंकर दवे]

पार्लियामेंट, जुडिशियरी और ऐक्जीक्यूटिव जो मेन फंक्शनरी हैं, आप सिविल कोर्ट से जुरिस्डिक्शन क्यों ले रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐक्सपोर्टर या इंपोर्टर हो यदि ब्यूरोक्रेट्स उनसे नाराज हो जाएंगे तो उनके पास क्या उपाय रह जाता है ? आप सारी स्पेशल पावर्स अपने पास ही रख रहे हैं । जुडिशियरी को कोई पावर तो दीजिए । मान लीजिए कोई ऐक्सपोर्टर या इंपोर्टर अपील करना चाहता है तो सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है तो हाई कोर्ट की बजाय आप सिविल कोर्ट में वह जा सके, ऐसा रूल्स में प्रावधान कीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन्तप्पा) उसका जवाब तो दे दिया ।

The amendment (No. 4) was, by leave, withdrwan.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The question is:

That clause 15 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clauses 16 to 20 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. J. KURIEN: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The House stands adjourned for one hour for lunch.

The House then adjourned for lunch at five minutes past two of the clock.

The House reassembled after lunch at five minutes past three of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY) in the Chair.

THE PLANTATIONS LABOUR (AMENDMENT) BILL, 1992

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Plantations Labour Act, 1951, be taken into consideration."

The Bill *inter alia* seeks to provide better welfare facilities, safety provisions to plantation workers and deterrent penal provisions for non-implementation of the welfare provisions of the Plantations Labour Act, 1951.

As hon. Members are aware, the Plantations Labour Act, 1951, whcih provides for the welfare of plantation labour and regulates the conditions of work in plantations was last amended in 1981 with a view to removing certain difficulties that were experienced in its working and for enlarging its scope.

After the aforesaid amendment, we received a number of suggestions from different State Governments for further amendment of the Plantations Labour Act, 1951. The difficulties in proper implementation of the welfare provisions of the Plantations Labour Act, 1951, were considered by the reconstituted Tripartite Industrial Committee on Plantation n March, 1983 which felt that the Act should be reviewed to ensure better medical facilities, housing facilities, protective clothing, etc., as well as adequate safeguard against the use of toxic chemicals which are being increasingly used in plantations.

In the light of the recommendations o the Tripartite Industrial Committee on Plantations and the provisions made in the Chlid Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, we have brought forward this Bill. The major proposals in thi Amendment Bill include making provisions relating to safety of workers and occupational health problems arising out of work in plantations, prescribing time limits within which garden hospitals and group hospitals should be established amendment of definition of 'Family' to also include dependants of female wor

kers, amendment of the definition of 'Workers' to include contract workers. The Bill also seeks to amend the definition of 'Employer' to include directors, partners, etc., including Government officers appointed to manage the affairs of plantation in order to pin-point the responsibility for any lapse in implementation of the Act and also make penal provisions more deterrent for the non-implementation of the provisions of the Act.

I hope the hon. Members would welcome the Bill. With these words, I commend the Bill for consideration of the House.

The question was proposed.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1951 में यह विधेयक अस्तित्व में आया था और 1954 से इसका कार्यान्वयन आरम्भ हुआ। लगभग 40 वर्षों के अन्तराल में, विभिन्न क्षेत्रों में, हर दिशा में, हमारे राष्ट्र में बड़े-बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और संबंधित विधेयकों और कानूनों में उसी प्रकार से आवश्यकता और समय के अनुसार संशोधन किया गया । आप जानते हैं कि हमारे देश का बहुत बड़ा भाग पठारी और पहाड़ी है । आम तौर से इस पठारी और पहाड़ी भाग पर दलहन, तिलहन या अनाज की फसल बहुत कम मात्रा में या न के बराबर या अधिक मात्रा में उगाई नहीं जा सकती है और केवल अनाज, तेल या दालों से ही इंसान न तो अपना पेट भर सकता है और न ही अपनी अन्य आवश्यकतायें पूरी कर सकता है । इसके अलावा मनुष्य को ईंधन की भी आवश्यकता होती है, फलों की भी आवश्यकता होती है, तारपीन की भी आवश्यकता होती है और पैरोजा की भी आवश्यकता होती है । इसके अलावा पशुओं के लिए चारे की भी आवश्यकता होती है । देहातों में काम की भी आवश्यकता है, उद्योगों की आवश्यकता है, पानी के जलाशय बचे रहें, उनमें कटाव न पैदा हो, पानी अधिक बरसे, यह भी आवश्यकता है । इसलिए जितनी हमारे देश में खेती की आवश्यकता है, जलाशयों की आवश्यकता है उतनी ही बागानों की भी आवश्यकता है और इस प्रकार की भूमि जो पहाड़ी और पठारी है या जो बंजर या बीहड़ होती चली जा रही है, इसमें आसानी से बागानों का रोपण किया जा सकता है, बगान लगाये जा सकते हैं । यदि बड़ी मात्रा में बगान लगाये जायें तो गांवों में लोगों को रोजगार मिलेगा, गांवों में उद्योग लगेंगे और जैसा मैंने पहले कहा, जलाशयों का कटाव भी बचेगा और पानी के जितने भी संसाधन हैं, वे सुरक्षित रहेंगे । इस आवश्यकता को आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भी जब उनकी हमारे देश में सरकार थी महसूस किया था और डेढ़ सौ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की कुमाऊं पहाड़ियों में चाय उगाने के लिये चीन से लोगों को आमंत्रित किया था और इस प्रकार से आमंत्रित करके केवल अस्थायी रूप से भारत में नहीं बुलाया था बल्कि यहां पर स्थायी रूप से आबाद करने के लिये बुलाया था । उस समय बड़ी संख्या में चाय कुमाऊं की पहाड़ियों में उगाई गई । लेकिन आज उसका लोप हो गया है ।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि 1943–44 में नदियों के किनारे, बड़ी ऊबड़ खाबड़ जमीन हैं जिनको हमारी भाषा में बीहड़ बोलते हैं। अगर आपको कभी इत्तफाक हुआ हो रेलगाड़ी से सफर करने का तो धौलपुर से ग्वालियर तक तो रास्ते से चम्बल नदी के किनारे जो ऊंचे-ऊंचे टीले हैं उनको बीहड़ बोलते हैं, वे बीहड़ 1943–44 में जितने थे वे और अन्य बीहड़ अब करीब 40 परसेंट हमारे देश में बढ़ गये हैं । और इसमें जो खेती के लायक जमीन थी वह नष्ट हो गयी है । इन बीहड़ों को बागानों के रूप में इस्तेमाल करके उपयोगी बनाया जा सकता है । मान्यवर, इस तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये और वहां बागान लगाये जाने चाहिये ।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : चम्बल घाटी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : वहां हम डकैतों से लड़ रहे हैं जिनको आपने पैदा किया है । . . (**व्यवधान**) . . .

But that was in previous times. It is not a problem of this day.

[श्री संघ प्रिय गौतम]

तो सर, मैं निवेदन कर रहा था कि बागान जितने भी लगे थे उन्हें जिंदा रखना चाहिये था, सर-सब्ज रखना चाहिये था और लोगों को बागान लगाने के लिये प्रेरित करना चहिये था। लेकिन हो गया उल्टा । जितने भी हमारे बागान थे वे उजड़ रहे हैं और नये बागान लगाने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है। जैस कि मैंने अभी कुमाऊं का उदाहरण दिया, इसका मुख्य कारण रहा श्रमिकों की बुरी तरह से शोषण। बागान में जो मजदूर काम करते थे, उनकी तरफ बागान के मालिकों ने इंसानियत की निगाह से नहीं देखा । उनके लिये पानी की व्यवस्था होती, उनके बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था होती, उनको पूरी मजदूरी मिलती और अगर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की अच्छी व्यवस्था होती तो वह तंदुरस्त रहते और वे उन बागानों में रूचि लेकर काम करते और उनको छोड़कर नहीं जाते। इससे बागान उजड़ते नहीं और नये बागान लगते और इस तरह का माहौल सारे देश में पैदा होता । मान्यवर, यह विधेयक जो 1951 का है, इसका संशोधन बहुत पहले हो जाना चाहिये था । आज यह बड़े विलंब से संशोधन किया जा रहा है, जब कि इसकी बहुत बड़ी सजा हमारे मुल्क को मिल चुकी है । मान्यवर, इस समय बागान लगाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जंगलों का कटाव हो रहा है और जंगल उजड़ रहे हैं । एक तरफ यह हो रहा है और दूसरी तरफ जमीन को खेती के लायक नहीं बनाया जा रहा है। बार बार इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया जाता है । मान्यवर, मैंने अनेकों बार इसी सदन में यह प्रश्न उठाया है कि जो जमीन खेती के लायक पड़ी हुई है उसको उपजाऊ क्यों नहीं बनाया जा रहा है । उसमें खाद डालकर, उसमें पानी देकर उस पर खेती करायी जाय ताकि देश का उत्पादन भी बढ़े और खाद्य के मामले में देश आत्मनिर्भर हो जाय और लोगों को रोजगार भी मिल जाय । लेकिन इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं गया । मान्यवर, इस जमीन का उपयोग बागान के रूप में किया जा सकता है । अब यह बहुत आवश्यक हो गया । मान्यवर, हमारे देश की उपज उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह दूसरे देशों की उपज बढ़ रही है । मुझे यह पढ़कर बड़ी हैरानगी हुई कि चीन में तीन करोड़ हैक्टेयर भूमि में 16 करोड़ टन चावल पैदा होता है जब कि हमारे यहां 4 करोड़ हैक्टेयर भूमि में केवल 6 करोड़ टन चावल पैदा होता है। हम कितने पीछे हैं इस मामले में ? मान्यवर, हमारे यहां जो जंगल है उनके बारे में बताया गया है कि 7 करोड़ 43 लाख हैक्टेयर जमीन में वन हैं जोकि पूरी भूमि का 22.7 प्रतिशत है। [उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए] लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो हैलीकाप्टर से सर्वे किया गया तो कुल 12 प्रतिशत ही वन पाये गये । तो मान्यवर, जब वन बहुत कम हैं और वनों में कटाव है तो फिर इसका विकल्प बागों के अलावा कुछ नहीं । यह कोई जरूरी नहीं है कि चाय और काफी के ही बाग हों, बाग जैसे मैंने बताया चीड़ के भी हो सकते हैं, हमें तारपीन चाहिये लकड़ी चाहिये । कागज बनाने के लिए भी हमें मेटिरियल चाहिए । हम कागज़ भी बाहर से मंगाते हैं। हमारे यहां कागज प्रति व्यक्ति जितना बंटवारे में आता है, अमरीका और इंग्लैंड में उसका सौ गुना, डेढ़ सौ गुना कागज़ प्रत्येक व्यक्ति के बंटवारे में आता है । आज हम कागज में भी आत्म निर्भर नहीं हैं । इस कागज के लिए बागानों से कच्चा माल प्राप्त हो सकेगा। जैसे यूकेलिप्टस से हमें ईंधन भी प्राप्त होता है और उसकी छाल से हम कागज भी बना लेते हैं। बागान केवल चाय या काफी के ही नहीं, फलों के बागान भी लगाए जा सकते हैं । फल भी अपने में आहार है, बहुत बड़ा भोजन है और पोष्टिक भोजन है, जिसकी हमें आवश्यकता है । इसलिए जहां इसके उद्देश्य बताए गए हैं, उनमें संशोधन करके य भी शामिल किया जाना चाहिए था कि हम श्रमिकों को सुरक्षा देना चाहते हैं, सुविधायें देना चाहते हैं ताकि वे जिन्दा रहे और बागान मालिकों में नये बागान

लगाने की रुचि पैदा हो। यह इस बिल के ओब्जेक्ट्स में जोड़ा जाना चाहिए था क्योंकि यह मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ओब्जेक्ट्स में इन बातों को भी जोड़ें। यह बताया गया कि 1991 में केन्द्रीय सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय के बागानों के लिए 9 अरब, 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। 25 जिलों में 50 हजार हेक्टयर भूमि में चाय के बागान लगाने थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? विधेयक में संशोधन लाने से क्या चाय के बागान लग जायेंगे? जब बागान नहीं होंगे तो विधेयक किस के लिए होगा? बागान के लिए ही तो विधेयक है तो बागान लगे या नहीं लगे और यदि नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे? यह मेरा कष्ट है। श्रमिकों का शोषण न हो और उनको पूरी सुविधायें मिलें। लेकिन मुझे कष्ट यह भी है कि बागान भी युद्ध स्तर पर लगें। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कितने बागान अब तक लगाए गए हैं? मुझे पता चला है कि केवल नैनीताल जिले में तीन नर्सरीज काम कर रही है और छोटे-छोटे चाय के बागान चार जगहों पर लगाए हैं जबकि ब्रिटिश पीरियड में सारे कुमाऊं से चाय बाहर भेजी जाती थी और सब से बढ़िया चाय होती थी। मंत्री जी ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि आजकल खेती में रसायन और कीट नाशक दवायें ज्यादातर इस्तेमाल होने लगी हैं। जब श्रमिक इन दवाओं का इस्तेमाल या छिड़काव करते हैं तो जानकारी के अभाव में इन दवाओं का कुप्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए आपने कहा कि उनको सुविधायें देंगे, अस्पताल भी बनवायेंगे। विधेयक में यह कहा गया है कि जो अपने बागान का रजिस्ट्रेशन करवायेंगे दो साल के बाद उनको एक अस्पताल बनवाना पड़ेगा, तीन साल के बाद एक दूसरी किस्म का अस्पताल बनवाना पड़ेगा लेकिन मंत्री जी, इसमें यह नहीं कहा गया है कि दो साल के अन्दर उसे स्कूल भी बनवाना पड़ेगा, दो साल के अन्दर पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ट्यूबवेल लगा कर पानी के टैंक बना कर पाइप भी बिछाने होंगे। इसमें यह नहीं कहा गया है कि जो स्थायी रूप से वहां रहेंगे उनके रहने के लिए मकान भी बनाने होंगे। यदि उनको दूध की जरूरत हो तो गाय भैंस रखने के लिए उन मकानों में स्थान भी उपलब्ध होंगे और आगे सेहन भी होंगे, किचन गार्डन भी होंगे जिसमें वह सब्जी भी उगा लें अन्यथा वे सब्जी कहां से लायेंगे क्योंकि वह तो चाय के बाग में काम करेंगे। इसमें यह नहीं कहा गया है। जब यह नहीं कहा गया तो क्या अस्पताल खोलने से श्रमिकों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। दवा के साथ रोटी, दवा के साथ सब्जी, दवा के साथ खुला मकान, दवा के साथ दूध, दवा के साथ शिक्षा, भी अति आवश्यक है। इसलिए इनके बारे में कोई समयबद्ध योजना, कोई समयबद्ध कार्यक्रम की बात मंत्री जी ने नहीं कही। यह भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर यह नहीं होता तो श्रमिकों का हित कहां रहा, केवल घड़ियाली आंसू होंगे, जैसे पहले से आप औपचारिकता पूरी करते आए हैं। ये भी इसमें मैन्डट्री बनायें। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हमारे यहां, बुलंदशहर जनपद में जहां का मैं रहने वाला हूं, नरोरा एटामिक पावर प्लांट बना। प्लांट की पूरी इकाइयां आज भी चालू नहीं हुई हैं, शायद 10 साल बाद चालू होंगी लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की कालोनी, दवाखाना, स्कूल, पेयजल की सुविधा ये सब दस साल पहले ही बन गये जब कि संयंत्र लगा भी नहीं था। जब इन अधिकारियों के लिए अनेकों सुविधायें हैं, संयंत्र के निर्माण के पहले ही यह व्यवस्था हो जाती है तो यह श्रमिक जो इस देश की धरती का सीना चीरकर हम लोगों की उदरपूर्ति करते हैं, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनके लिए यह चीजें शुरू में ही क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती हैं। इसलिए, मान्यवर, मंत्री महोदय से इस बात के आश्वासन की इच्छा और आशा रखते हुए कि दोबारा इसमें संशोधन की आवश्यकता न पड़े, आप नियमों के द्वारा या किसी अन्य तरीके से इन सारी व्यवस्थाओं को

[श्री संघ प्रिय गौतम]

भी सुनिश्चित करेंगें, कि इम्प्लायर उनको पैसा तो पूरा देगा ही, ठेकेदार भी पैसा देगा, सब चीजें होंगी लेकिन ये उपयोगी वस्तुयें और आवश्यकतायें हैं ये भी सुनिश्चित होंगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, Hon'ble Minister for Labour Shri Sangma has brought the Plantation Labour (Amendment) Bill for discussion here keeping in mind the welfare of the Plantation workers. At this point of time, it is worthwhile to do some retrospection and see how well the original Act was implemented. This Act was originally passed by the Parliament in 1951. But it was not implemented until 1956. Meanwhile, the Tea Plantation labourers in Assam launched an agitation demanding that the Plantation Labourers Act be implemented. The agitation went on, in which about 50 labourers lost their lives. Only then the Government came forward to implement the Act. Yet, the labourers could not get the benefits of the Act because, there were practical difficulties in implementing the Act. Therefore, in 1973, an amending Bill was introduced in Parliament. Because of the importance of the Bill wanting serious deliberations, it was referred to a joint Select Committee of both the Houses of Parliament. But the Bill came back from the Select Committee for consideration by Parliament only in 1981, after a full 7 years. I am compelled to refer to the background only to highlight the nature of obstacles coming in the way of implementing the Act.

Sir, unfortunately the State Governments did not implement the Act in the way it should have been. That is why, as one having soft corner for the labourers, our Hon'ble Minister has brought in a welcome Bill. This amending Bill has provisions for providing residential accommodation and hospital facilities to the workers and their families. The living conditions of the Plantation labourers is really pathetic. Be it in Assam, Kashmir, Kerala, Tamilnadu or any part of the country, these unfortunate people live in misery. The Bill says that a plantation owner havnig 5 hactares of garden employing 15 workers will fall under the purview of this Act. But I wish to point out as to how the plantation owners will escape the hands of law. For example, in Kerala the plantation owners divide their estates into small measures of 2 hectares or so and register it in the names of relatives. This is how they remain outside the purview of law. As a result, the workers loose their concessions and privileges. I request the Hon'ble Minister to ponder over this and take some effective steps. By common sense, If someone has even two hectares of plantation, be it tea, coffee, cardamom or rubber, he needs to employ atleast 15 workers in the garden. But if he claims to employ less number of workers it is untrue.

We have to see to believe the kind of life they lead. Away from the estates, they live in jungles without even basic amenities. They have to walk over 6 Kilometres to the place of work. Now, the Bill speaks of providing them accommodation close to the place of work within the precincts of the plantations. But this provision should not go unimplemented like other provisions of the original Act. While the original Act provided for 12 hours of work each day this amending Bill speaks of 10½ hours of work. Then on the other hand, the Minister speaks of only 8 hours of work per day. I am at a loss to understand the contradiction. I request the minister to clarify this point.

Sir, discrimination amongst workers is a matter of serious concern. We have no reason to underrate the plantation workers as aaginst the industrial workers. We just can't justify such discrimination. Indeed, working in the gardens requires a great skill. It is not easy to pluck tea leaves unless one is trained and has the skill. I had an opportunity to go to Assam and see how the labourers toil in the tea gardens there. They sweat out in scorching Sun to pluck the leaves and process it. The industrial workers have atleast some kind of a shed to work in. But the plantation workers have to bear the on-

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

slaught of the vagaries of nature. Whether snake bites or scorpion stings, they have to do their work.

The workers of exploited in many ways. They do not get the wage actually mentioned against their names in the pay roll. Since they are illiterates, they affix their thump impression at the place indicated by the owner or manager and take home a meagre salary. They don't even know how much is due to be paid to them. This apart, their children are also being exploited. I am happy that this Bill phohibits child labour in plantations. But unfortunately there is compelling situation in the families of labourers to send their children to work to earn their bread. We have to do something substantial to change this situation. We earn lot of foreign exchange by exporting tea, coffe, rubber and cardamom. But we foreget the welfare of the workers who toil in the fields to produce them. Estate owners earn crores of rupees through export. But the workers are not given even one percent of the total income as wage. That is why over 20 lakhs plantation labourers all over the country lead a miserable life to this day. Most of them live on hilly regions without even basic amenities. They have no potable water and medical facility at the place of work or residence. There is no educational facilities for their children. We have to gracefully admit that the situation is much the same in both public sector and private sector plantations. The public sector undertakings like Tea Board and Coffee Board should come forward to implement the Act in total and thus set an example for the private sector to follow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Minister, he has made a very important point regarding the public sector. If you do not follow, how can you compel others to follow? Please loo into it. And you have to reply to that. He has made a very serious point.

SHRI V. NARAYANSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, most of the workers kept as casual labourers only to deny them their rights. Stern action will have to be taken against this exploitation. Sir, these plantations have to be protected against the attacks of pests and the growth of weeds have to be curbed in order to have good yield. For this, pesticides and herbicides have to be sprayed regularly. But who does this risky job? It is the children of the workers in the age group of 15-18 who are asked to do this dangerous job. Those children do not even know the harmful effects of the pesticides and cannot protect themselves by taking adequate safety measures. It is a matter of relief that child labour is banned in plantations through this Bill.

I have a point regarding compensation. There is a provision for compensation to workers in case they stand to loose their job for any reason. The Hon'ble Minister has said that an amount of Rs. 20,000 would be paid by the employer to the affected worker as compensation. But there is no mention of compensation in case of death of workers. I request the Hon'ble Minister to look into this matter. Since the minister has great concern for the workers. I appeal to him to take steps to register the union of plantation labourers. Then alone they will be able to fight for their rights.

It pains to note that the original Act has not been implemented for the last 30 years. Hon'ble Sangma and also the Deputy Minister have keen interest in improving the working and living conditions of the labourers. I have great hope that they will not leave any stone unturned to implement this Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Give chance to the minister to implement it. He has so much concern over the labour problems. Please give him a chance to impltment it.

SHRI V. NARAYANASAMY: That is why I am saying Mr. Sangma is taking keen interest in labour related issues. I raised it from that point of view.

I wish to emphasis just one point. The Hon'ble Minister should take effective follow up action to implement this

[Shri V. Narayanasamy]

Act. I am hopeful that he will do so in spite of the obstacles ahead. Thank you.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Sir, as I rise to speak on The Plantations Labour (Amendment) Bill, 1992, I have a few points to make. I was going through the Statement of Objects and Reasons and also the proposed Bill. Actually this Bill wants to amend the Plantations Labour Act, 1951 which was enforced from 1954. In this Bill some new clauses and provions for health and welfare are being included specifically after Chapter 4, a whole new chapter 4A is being included captioned as ' Provision as to safety'. Under the amendment, the employer is required to guarantee some safety measures for the workers while they are handling, using storing and transporting insecticides, chemicals and other toxic substances. There are other provisions also as to who will give them training, how they will be trained, what has to be done about the use of toxic chemicals, etc.

Here, I would like to draw your attention to a few facts concerning the plantations. Both the Minister come from tea plantation area. I would confine myself to the tea plantations because I was born and brought up in my childhood in Assam, in a tea plantation area itself. As you know, the tea plantations employ a large number of workers. In fact, it is a labour-oriented industry. More than 10 lakh workers are employed in these plantations, as permanent and casual labour, in Assam, Arunachal Pradesh, Tripura West Bengal, some parts of Uttar Pradesh—Pithoragarh, Kumaon, etc.—the Kangra Valley in Himachal Pradesh and Nilgiries in the South. The total land area covered by these plantations is 4,21,140 hectares, with a total yield of 714.61 million kgs., in 1990.

Sir, as you know, tea is a mass consumption product. It is also an export product. It earns good foreign exchange for India. In these plantations, particularly, in the North and North-East, where three-fourth of the workforce is there and which accounts for seventy-five per cent of the total tea production in India they are all migrant labour. Most of the workers had gone there as indentured labour from the Chhotanagpur area of Bihar. I have seen with my own eyes the plight, the condition, in which they live. The original Act, the Plantations Labour Act of 1951, somewhat protected their rights. The existing labour law provisions have failed to protect them from exploitation. More than half the workforce consists of women and children, including adolescent boys and girls. Particularly, women are an exploited lot. They are also sexually exploited. A large number of workers are children below 14 years of age. The Child Labour (Abolition) Act does not consider the work in plantations as hazardous.

Sir, the employers do not care about the safety and health of the workers. Medical facilities are inadequate. Even where there are hospitals, the facilities available there are inadequate. They suffer from lack of medicines. Doctors are not there. Nurses are not there. Really, nobody cares for the workers. The health and safety problems are being compounded by the growing use of agro-chemicals such as pesticides and herbicides.

The present amendment, as I said, contains safety provisions in regard to storage, handling and utilisation of agro-chemicals. We all know that after 1967, when almost half of India reeled under drought conditions, we had gone in a big way to increase food production. We launched the Green Revolution. This Green Revolution wave also touched the plantations. But after the Green Revolution and the 'Grow More' slogan, India has been importing agro-chemicals—pesticides and herbicides—in huge quantities. Sir, you know that developed nations have been dumping their obsolete and harmful agro-chemicals in the developing countries, includnig India. The quality of agro-chemicals, pesticides and herbicides, that they do not use in

their own country, are dumped in these countries and we have seen their bad effects on our products. The International Labour Organisation for the last ten years has been advocating banning of hazardous agro-chemicals. They have also passed a convention in this regard. Although India is a signatory to almost all the ILO conventions, we have never implemented them fully. We are still using a huge amount of pesticides and herbicides in our agricultural activities, including tea plantations. The National Industrial Committee on Plantation Industry has also been discussing this issue, but they have not arrived at any positive conclusions so far.

Now, I congratulate Mr. Sangma as he has given some thought on this and he has brought forward this Bill. The tea gardens are scattered in large areas. Mostly spraying is done by hand. What do they do with the sprayer? They tie the portable chemicals-spraying machine on their backs and use their hands to spray. What happens? They go on spraying, with the result that the vibration caused by the machine affects their body system. Nobody bothers about that. There is one more thing. While spraying the medicines, the pesticides and agro-chemicals the management should supply them with adequate protective measures. For example, they must be supplied with gloves, masks, goggless gum boots and jackets which could cover their bodies, but it is not done anywhere. I have not seen anywhere, in any plantation, any management supplying these items to the workers who are spraying these toxic items. Our junior Minister is here. He also comes from a plantation area. I do not know whether he has seen it or not, but I have not seen it. Last January I was in Sri Lanka. I saw some of the very developed tea gardens, but there also these things are not being used. So, the tea garden owners do not bother for the health and safety of their workers.

There is one more point. After the primary spray, a second spray is done. Within a week or ten days of the second spray tea leaves are ready to be pluked. It takes seven to ten days for the tea plants to absorb the toxic medicine, but the owners, the empolyers, are in a hurry. They do not wait for such a long time. So what happens? Immediately after three to four days of spraying pluking starts. Plucking is mostly done by women, small boys and girls. They do the plucking and they get infected. They get various kinds of skin diseases. Also adverse effect has been seen on finished products. Toxic materials are found on the readymade tea which we consume, which we sell outside. Only in 1984-85 a few consignments returned by Germany and other countries. So, quality control is also not there. The quality control of the finished product is also not cared for by the owners, by the employers, of these gardens. Now, who will look after these things, who will monitor it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Then, I think, we should stop taking tea.

SHRI V. NARAYANASAMY: If you go to the plantation area, you will forget it.

SHRIMATI KAMLA SINHA: We should go in for...

AN HON. MEMBER: Coffee!

SHRIMATI KAMLA SINHA:... Organic chemicals and natural manures rather than using herbicides and pesticides and toxic chemicals. They don't help us. They are also destroying our ecological balance and environmental balance. The natural insects which used to protect the plants are dead now. So, we need there new organic environment friendly chemicals.

What is happening now? I told you, Sir, that women and adolescents in large numbers become victims of skin diseases and various other diseases and also pregnant women, in the early days of pregnancy and late on also, become victims of these diseases and it has been found that even unborn children get infected. So, this is a very dangerous situation.

[Shrimati Kamla Sinha]

Sir, I would like to draw your attention to a provision of the Bill in the same Chapter with regard to safety—clause 18A (3). It says, "The employer shall appoint persons possessing the prescribed qualifications to supervise the use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances in the plantation." Now, who is going to monitor it? These are all private owners. We are going in for privatization, but plantation is already in the private sector. Hardly any Government-owned plantations are there. So, who is going to monitor it? Till now there has been no machinery to do it. As of today, plantation workers do not get proper drinking water; they do not have proper residential quarters. They do not live like human beings. They are still living like indentured labour, bonded labour. Only this morning the Minister was answering questions on bonded labour. If there is really any bonded labour, it is this plantation labour who are bonded labour. So the Minister will have to evolve a proper machinery to monitor all these things. And who will certify that certain persons are qualified to supervise and give training—managerial staff—for the workers. Who will do it? We know that these days, even at the highest level, the family rules supreme. So, in most of the cases the employer's family members are employed as managers, supervisors, etc., etc. So, who will ensure that the people who are being employed are really qualified persons and they are really doing their job? So, merely passing a Bill won't help. We are passing many, Bills, we are enacting many welfare measures, but they are not being implemented properly. The most important part is proper implementation and that is not being done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now the last point.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Okay, Sir, I will try to finish very soon.

Now, Sir, some penal provisions have been made here. I would like to draw your attention to clause 11 on page 6 of the Bill. Now, everywhere people are working for eight hours a day. Here in this Bill, in clause 11 (a) it is stated, "for the words 'twelve hours', the words 'ten and a half hours' shall be substituted."

4.00 P.M.

What is this nonsense? I would like Mr. Sangma to clarify it. Are the plantation workers working for 12 hours a day? Is it not a violation of all our laws? They should be working for 8 hours a day. Then the Bill says:

"..."ten and a half hours" shall be substituted;" I would request the Minister to amend it and write "eight hours a day", not "ten-and-a-half-hours a day"

In another clause, clause No. 21, the penal provision is:

> "six months or with fine which may extend to ten thousand rupees..."

instead of "six months" if you really want to punish violators of this law, then, it should be very very strict and stringent. So, this punishment should be for one year, not for six months.

Then, there is child labour. I have an apprehension, Sir, This Bill wants that no women and children should be employed between 7 P.M. and 6 A.M. Chapter V says:

> "Except with the permission of the State Government, no woman or child worker shall be employed in any plantation otherwise than between the hours of 6 A.M. and 7 P.M."

No women works after sunset. As far as I know, plucking goes on during day—time, during the period of sunlight. So, this provision has some black meaning behind it. I have a feeling that you want to retrench women workers and child labourers. The Child Labour Abolition Act provides that no child under 14 should work, but, then, as far as plantation goes, it has been thought that it is really not

a hazardous work and that child labour can be employed in plantations. This Bill says that adolescent can work. That means one over 14 years of age.

This is section 22. I have a feeling that women workers are going to be retrenched. On many pretexts, on the pretext of hazardous work, from various fields, textiles, coal, mining, women have been elbowed out. Their number has gone down. This is only one sector where 50 per cent of the workers are women. So, I would like to have an assurance from the Minister on the floor of this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Minister, she wants some assurance.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Mr. Minister, I am drawing your attention to this, and I would like to have an assurance from you on the floor of this House that no women would be retrenched because of passing of this Bill.

Another thing I would like to say is, Sir, that it is very good that we are passing this Bill, but these workers, as I said, are all indentured workers. They have been taken from various parts of the country. Especially in the North-East they have gone from Bihar and Chhota Nagpur plateau. These people have not been amalgamated into the local society. No local legislation, no panchayat provision covers them. They get no benefit of local legislations or other measures that have been miplemented in this country for employment better facilities of life, the IRDP, the NREP, TRYSEM etc. etc. Unemployment is also growing among the plantation workers. Among the plantation workers, the young generation is coming up, and the garden employers cannot absorb them. They cannot find jobs there. So, new jobs have to be created for them. For that, new evenues will have to be created for them. If they are absorbed in the schemes of the IRDP, the NREP, and the TRYSEM etc., some employment will ne created.

So, I would like the Minister to take these points into account and do something about them. Otherwise, it is good to pass a good Bill, but, as I said without proper implementation this will become another piece of academic exercise, and it will be good to have it in the library. Thank you.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, बागान श्रम संशोधन विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब से हमारी संस्कृति शुरू हुई है, तब से हम कहीं न कहीं कृषि समाज से जुड़े हुए हैं और जब से हमारे खानपान में परिवर्तन हुआ है तब से शायद हम लोग चाय के साथ भी जुड़े हुए हैं। यह बागान श्रम संशोधन विधेयक जो है, इसमें सबसे ज्यादा इन्वाल्वमेंट चाय बागान लेबरों का है। करीब 8 लाख 22 हजार से ज्यादा लोग चाय बागान वरकर्स इसमें इन्वाल्व हैं। महोदय, मेरे बचपन का कुछ वक्त असम में गुजरा है और मुझे इन्हें देखने का मौका मिला है और मैं समझता हूं कि चाय बागानों के मजदूरों की जो प्राब्लम है, ऐसा इत्तफाक है कि जो मंत्री महोदय चाय बागान संशोधन विधेयक ला रहे हैं, ये खुद उस इलाके के हैं। इन्होंने वहां की मुसीबतें झेली हैं और वहां की मुसीबतों को झेलते हुए ये बड़े हुए हैं और उन्हीं चाय बागानों में फले फूले हैं। मैं श्रीमती सिन्हा से एग्री नहीं करता, जैसा कि उन्होंने कहा कि हजारीबाग और छोटा नागपुर इलाके के लोग वहां जाकर मिक्सअप नहीं हो सके हैं। मैं जहां तक श्री पवन सिंह घटोवर को जानता हूं, इनका परिवार 150 साल पहले असम गया था और चाय बागानों में ही काम करने के लिए गया था। आज वे वहां से लोकसभा में निर्वाचित होकर आये हैं और इस देश के मंत्री बने हुए हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा : कितने ऐसे मंत्री बने हैं ? इनके अतिरिक्त और उदाहरण बता दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : चाय बागानों से जितने भी एम.एल.ए. है वे सब बिहार के हैं ?

श्रीमती कमला सिन्हा : कौन हैं जरा बताइये ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : 15 एम.एल.ए. और 5 मिनिस्टर हैं असम में जो बिहार के इलाके से वहां गये हुए हैं और चाय बागानों वाले इलाके में रहते हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा : कहां के लोग हैं ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उड़ीसा से हैं, छोटा नागपुर इलाके से हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा : जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल गया वे ऊपर हो गये। बाकी लोगों का क्या हुआ ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपने जो कहा मैंने उसका जवाब दिया।

श्रीमती कमला सिन्हा : आपका जवाब सही नहीं है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वहां पर वे मिक्सअप हुए हैं। वहां पर कोई विभेद नहीं है, कि असमी है या देशवाली है। वहां की पापुलेशन के साथ वह मिक्सअप हो गये हैं, वहां समा गये हैं और वे अपने आपको असम का असमी समझते हैं और वहां काम करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राबलम का सवाल आता है तो क्योंकि बागानों में और ऐसे खेतों में प्लांटेशन में शुरू से ही कुछ न कुछ खामियां रहती रही हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानते हैं या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अत्याचारों को जानते हैं, उनको पता है कि इंडिगो प्लांटेशन, जो हमारी कन्ट्री में नील की खेती होती थी, वे मैनचेस्टर में अपने कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, या कपड़ों को रंगने के लिए नील की खेती भारत में कराते थे, और इसकी खेती भारत में होती थी और जिसका ज्यादा भाग बिहार और अविभाजित बंगाल में हुआ करता था। उस नील के खेती के कारण वहां की जमीन खराब हो जाती थी और वहां के मजदूरों पर बड़े बड़े अत्याचार होते थे। उस वक्त भी उस नील की खेती के लिये पेस्टीसाइड और इन्सेक्टीसाइड का यूज किया जाता था। उससे भी मजदूर ग्रसित होते थे और इसके कारण चम्पारन में महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ। चम्पारन का जो महत्वपूर्ण आन्दोलन है उसके पीछे भी यही एक कारण था। 8 घंटे में से 6 घंटे उनको नील की खेती में काम करना पड़ता था और दो घंटे धान की खेती में काम करने का मौका मिलता था। यह शोषण और अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सिखाया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो इस देश से चला गया मानचेस्टर के कारखाने गांधी जी के खादी आन्दोलन के बाद बंद हो गये। आज मानचेस्टर देखने में भूत बंगला लगता है, जहां पर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल की मिलें थीं, आज किस तरह से जंकयार्ड बन कर पड़ी हुई हैं। पर जाते जाते वह कुछ साहबनुमा चाय बागान के मालिकों को छोड़ गये। चाय का उत्पादन करने के लिए यह जरूरी होता है कि कीड़ों, मकोड़ों और दूसरी टिड्डियों से बचाने के लिए उस पर इनसेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्स का छिड़काव करना पड़ता है। इसका असर इनवार्यनमेंट पर भी पड़ता है और उस इलाके पर भी पड़ता है। जो आदमी वहां काम करता है, उस पर तो बहुत जोरों से असर पड़ता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिल तो आप लाए, इस बात को समझ कर लाए। मेरा कहना यह है कि अगर दिल्ली में भी किसी आदमी को पेस्टीसाइड या इनसेक्टीसाइड का असर हो जाए और वह मूर्छित हो जाए या इसका असर उसके खून में चला जाए या वह इनहेल कर ले या स्वेलो कर ले तो उसके लिए एंटीडोट मेडिसन कभी कभी दिल्ली में भी उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि यह जापान, कोरिया, जर्मनी से आती है। जब दिल्ली में भी उपलब्ध नहीं है तो दूरदराज के चाय बागानों में या काफी के बागानों में या रबड़ के मैदानों में कैसे मिलेगी ? इसके लिए क्या प्रावधान

है? सरकार कैसे उनको मेडिसन दिलवायेगी, यह भी सोचने की बात है। आपके पास अस्पताल और ऐसे ट्रेंड आदमी जो सिर्फ इसी चीज में डील करते है, टोक्सीकोलोजी साइंटिस्ट हैं, वह कितने हैं? टोक्सिक कंडीशन से अफेक्टेड जो लोग हैं, उनको ठीक करने के लिए उनके पास सारे उपकरण उपलब्ध हों और इनको दूरदराज के चाय बागानों तथा काफी बागानों में उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान है तथा उसको मोनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? आपने अब तक कम्पनसेशन का कोई प्रावधान नहीं रखा। अगर कोई मज़दूर इनहेल कर लेटा है तो आपका सीधा सा बड़ा सरल जवाब आएगा कि जनरल वर्कमेंस कम्पनसेशन एक्ट के तहत उस को मुआवजा दिया जाएगा। मैं मानता हूं, ठीक है, जनरल वर्कमेंस कम्पनसेशन एक्ट आपने बना रखा है किन्तु उसके लिए जहां नार्मल कंडीशंस हैं या जहां पर एक्सीडेंट की सम्भावना नहीं है, कहीं हड्डी टूटने की सम्भावना नहीं है, कहीं लंग्ज खराब होने की सम्भावना नहीं है, कहीं हार्ट पर असर पड़ने की सम्भावना नहीं है, आंख, नाक कान खराब होने की सम्भावना नहीं है, उसको भी वही कम्पनसेशन और जहां खराब होने की सम्भावना है वहां भी वही कम्पनसेशन! यह कैसा कानून है? एक ऐसे माहौल में आप मज़दूर को काम करा रहे हैं जहां वह जानता है कि यह खतरा है। शराब की बोतल पर लिख देते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन जो पी रहा है वह जानता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पर लिख देते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन वह जानता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या आप चाय बागान में नौकरी के लिए यह लिखेंगे कि यहां काम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डोंट टेक दिस सर्विस। आप क्या करने जा रहे हैं? आप इनके लिए अलग कम्पनसेशन एक्ट का प्रावधान रखें और उसके तहत कम्पनसेशन देने का बन्दोबस्त करें नहीं तो आपके इन टी प्लांटेशन, कोको प्लांटेशन रबड़ प्लांटेशन या काफ़ी प्लांटेशन में और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटेशन प्रोग्राम में क्या फर्क रह गया? 1951 में आपने यह एक्ट बनाया और समय समय पर इसमें संशोधन किये लेकिन आज तक इसके बारे में नहीं सोचा। हम अगले कुछ दिन बाद पाल गैस लीक पर एक बिल लाने जा रहे हैं। यह गैस कैसे लीक हुई? यह क्या बनाते थे? यह यही पेस्टीसाइड्स और इन-सेक्टीसाइड्स बनाते थे या केमिकल्ज बनाते थे जो इन चीजों में काम आते हैं। हमारी आंखों के सामने ऐसी घटनायें घटी है जो लोग भोग रहे हैं। और इसका असर एक दिन दो दिन का नहीं होता, यह कोई मच्छर का काटना नहीं है कि मलेरिया हो गया और क्लोरोक्विन खा ली तथा छः दिन के बाद बुखार उतर गया। एक बार अगर आदमी पेस्टिसाइड्स इन्सेक्टिसाइड्स की स्मेल को इन्हेल कर ले तो उसका असर एक साल दो साल बाद भी आ सकता है। आपकी आंख खराब हो जाए, आपका सुनना कम हो जाए। आपका एक हाथ काम करना कम कर दे। ये असर हो सकते हैं। वैसी अवस्था आने पर क्या कम्पेनसेशन जज करेंगे, आप यह सोचिए। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा 1960 में नार्थ बंगाल में जो नक्सलवादियों का आंदोलन हुआ, उसके पीछे यही शोषण था। नक्सलबादियों का आंदोलन नक्सलबाड़ी के इलाके से जब हुआ तो वहां के जो चाय बागान के इलाके थे वहां से इनका असली आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने खा कि ये शोषक समाज के लोग जो चाय बागान के मालिक बैठे हुए हैं ये किस तरह से उन पर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से उनकी सुविधाओं को उपलब्ध न करा कर, उनसे वंचित रखकर उनका शोषण कर रहे हैं, किस तरह से चाय को एक्सपोर्ट करके तरह-तरह से अपना लाभ कर रहे हैं तथा इनका शोषण कर रहे हैं। उसके लिए आवाज उठाने के लिए उनको तैयार किया। वे एक सशस्त्र विप्लव के नाम पर खड़े हो गये। उसी तरह से खड़े हुए जिस तरह से चम्पारन में इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ हमारे बिहार के लोग खड़े हुए थे और गांधी जी की आवाज पर आंदोलन शुरू हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा मौका क्यों मिले

[श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया]

कि लोगों को शोषित करने का मौका आए। अभी तक, अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो मिल मालिक, चाय बागान के मालिक बैठे हुए हैं या काफ़ी बागानों के मालिक बैठे हुए हैं ये इस तरह से नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं।

इस बिल में सिर्फ प्लांटेशन की बात है। किंतु प्लांटेशन के साथ-साथ मैं जहां तक जानता हूं, चाय, काफ़ी, कोकोआ, और रबड़, इनके बागानों के साथ-साथ इनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होती हैं अगर इनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स को देखा जाए तो इनमें भी तरह तरह के प्रोसेस ऐसे है जिनका इफेक्ट ह्यूमन बाडी पर, ह्यूमन लाइफ पर पड़ता है। उससे प्रोटेक्शन के लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कम से कम इतना क्लियर कर दें और हम लोगों को बतायें... **(व्यवधान)**

Sir, can I have your attention, please?

इन्होंने कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं बताया है। मैं इतना जानना चाहूंगा कि कितने दिनों के अन्दर इस तरह का इलाज करने के लिये अस्पताल लग जायेंगे या कितने दिनों के अन्दर जैसे लोगों का इलाज करने के लिये या वेल्फेयर के लिये वहां पर आदमी बहाल कर दिये जायेंगे और उनका टेन्योर क्या रहेगा। इन सबका प्रावधान आपने अब तक नहीं बताया और कब तक करेंगे? यह तो कह देंगे कि हमने बिल पास कर दिया, प्रेजीडेंट का असेंट हो गया और लागू हो गया। लागू तो हुआ लेकिन वहां इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि चाय बागानों के मालिकों के पास अभी तक इतना पैसा है कि ये लोगों की हथेलियों को गर्म कर सकते हैं और जो संदेह सब. सदस्यों को है वह संदेह मेरे को भी हैं कि यह कानून शायद हथेलियों पर गर्मी चढ़ने के बाद लागू नहीं हो। मंत्री महोदय चूंकि उस इलाके के हैं और उस समाज से आते हैं तो अपने साथियों और अपने भाईयों पर पूरी कृपा करने के लिये, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाय, उसका बन्दोबस्त करें तथा एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर इसको लांच करें। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देशाई): अभी जब बताया इसके बारे में, मुझे याद है कि मैं करीब 10–12 साल का होउंगा, गुजरात में एक पुस्तक थी उसका नाम था, चाय यानी मजदूर का लहू।

I read that book. After reading that, even though I was a boy of about 10 years of age, I was very sorry about the kind of exploitation that was going on in tea gardens. Because of such exploitations only, Members speak on these lines.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Sir, I find that this Bill came up for consideration after a news-item that we read in the newspapers that Indian tea fetched a price of Rs. 10,001|- in the international auction market some time back. It shows the rate of profitability that is there in this industry, in the plantation, industry, particularly tea, and the rate of explotation that is there at the cost of the workers. So we must stand unitedly to fight against all the problems, against all the practices that lead to further exploitation of the workers in work and out of work-both ways.

Now, this Act has been there on the Statute book for a pretty long time and if we take Shrimati Kamla Sinha's figures as correct, then there is a difference between the official figures and the figures given by her. The official book—Handbook of Labour—1990, gives us a different figure. It shows that if we take tea coffee and rubber plantations together the total number of persons employed in these industries is 5,80,000 of whom 4,21,000 are women. I think that this figure also is to be corrected. It shows that perhaps the Act is not applied in other plantations. That is why these figures are also not with the Government. The responsibility of making the Act applicable to all plantations rests with the Government and unless the Government does it, there will be no necessity of such

Acts and whether these Acts are on the Statute book or not, they do not affect the life of the workers. The Act becomes powerful not only by passing a Bill but by having a political will to implement those Bills after being passed. On that depends whether it will serve the purpose or not.

Much has been said about the problems of the workers. I do not want to repeat that. I only want to draw the attention of the Minister to the Monograph—Shram Shakti—whcih was published in 1988, that is, the report of the National Commission on Self Employed Women and Women in Informal Sector. It graphically states: What are the problems of workers relating to their health in plantation, what are the consequential results of those problems and what are the recommendations for removing those problems? I am quoting from that book.

1. "Occupation and some causal factors: Inhalation of dust, exhaustion due to heavy workloads, further increased by piece-rated wages by high environmental temperature and humidity lack of health and medical services and working bare-foot. It causes health problems such as lung infections and bronchial problems, physical stress, malnutrition, Helminthie infestations, dysentery, contact dermatitis nd other contact diseaese, heat stroke, ligh incidence of maternal and child mortality."

The recommendations of the *Shram Shakti* are:

"Regulation of hours of work through guaranteeing a living wage and regular employment; provision of personal protective equipments; provision of health and medical facilities alternate work allocation during and after pregnancy and warning and training about the use of chemcals."

As, regards tea-pickers, as Shrimati Kamla Sinha Ji told us that they work with unsafe chemicals in unsafe work terrains. As a result, insects and snakes bite them, and they suffer from allergies; occupational of bronchi pesticides hazards, accidents and falls due to steep slopes and pain in back due to carring heavy loads.

They have recommended that provision of personal protection equipment should be there. There should be reduction in workload by providing a living wage on a daily or time-basis and there should be a provision for medical and health facilities. So these two aspects are here brought out in focus by this Shram Shakti Report—that the safety and the working conditions and the wages are interlinked. There cannot be any safety if the worker is not strong enough to even carry his equipment. We have seen that in spite of very well defined, codified Act in mining industry, the welfare and safety provisions are generally not implemented. So in plantation, however good a Bill may be, unless the infrastructure is built up, there will be no implementation. For example, a provision for "garden hospital" and "group hospital" has been made in the Bill. Now what is the number of gardens to be covered by this? The number of gardens to be covered by a 'group hospital', the size of its commanding area, all these things are not defined in the Act. Unless these things are defined, these will only be resulting in violation and nothing else. The owners will not implement on the plea that the provisions are not categorical.

Now what diseases are there to be taken care of? In other industries also, as the hon. Minister may be aware, as, for example, in the Mines Act, some diseases are recognised and for the treatment of those diseases, as per the Act, there are some provisions made, but in practice those provisions are not implemented. Here also, we must take special care so that the occupational diseases are identified and an arrangement for their proper treatment should be made so that the workers do not have to suffer due to non-availability of treatment. There are other problems of housing and non-employment of children. The question of wages is also there. If you do not pay sufficient wage enabling the workers and their families to have nutritional food sufficient to pull up, they will be bound to violate the certificate and get their children employed in the plantation. This will be the result. Unless we pay them sufficiently to live comfortably unless

[Shri Sunil Basu Ray]

we do it, unless the Government takes care of it, there will be no implementation of this Act.

The next question is about the working hours. The working hours should be reduced. The number of weekly working days should be reduced and the number of daily working hours should also be reduced. If we do not do that, we will not be doing justice to the cause that we are espousing here. If we do all these things, only then can we talk of helping the workers and also the poor and the down-trodden people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri David Ledger. Five minutes only.

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. The Plantations Labour Act 1951 was passed to provide for the welfare of labour in plantations and to regulate the conditions of their work.. *(Interruptions)*.

SHRI MOHD. KHALEELUR REHMAN (Andhra Pradesh): Perhaps you are going to make your maiden speech.

SHRI DAVID LEDGER: I have to. Maiden speech as a Congress Member. That is right.

Sir the Act has been in force for almost 40 years but it became operative from the year 1954, but how far the Act has succeeded in dealing with the welfare of the labourfi class of the gardens is a matter of doubt. This Statement of Objects and Reasons laid down by the hon. Minister says that the Act did not contain any provision for dealing with the safety of the working class. Nor did it provide any safeguard for those workers in the plantations who handle hazardous substances like agro-chemicals mainly insecticides and herbicides of various kinds. So, by amending this Act certain safeguards in these lines are sought to be provided.

Sir, I belong to a State which produces approximately sixty per cent of the country's tea. At a distance of only 15 kilometres from my house, there is a tea garden. I have studied with the boys of the garden, I have grown up with them, I have seen their plight and I have seen their living conditions. We all know that Assam Tea is a major source of earning foreign exchange for this country. There are more than three million workers in the various tea gardens, and the coffe gardens of Assam. It is a huge workforce by any standards. But after 45 years of independence we have seen that precious little has been done for the welfare of these workers. Be it health, be it education, the plantation sector has always been deprived of the facilities which are available to the other sectors of industry. The garden workers always remained neglected. There is no proper facility for schooling. The garden workers have to live in poor health conditions as has been mentioned by a couple of of hon. Members. Housing provisions are still in a very pathetic condition. There is only about 60 per cent standard housing facility in the tea gardens of Assam. Electricity facilities cannot be compared to those in any other industrial sectors and the garden workers are practically living in darkness even at the end of the 20th century.

Sir, I have already stated that the Act had been in force from 1954 and the responsibility of implementing various provisions of this Act lay with the State Governments. But we have seen that the State Governments have not been discharging their responsibilities properly. The management of the plantations the management of the various gardens have been taknig full advantage of this weakness of the State Governments this negligence of the State Governments.

[The Vice-Chairman (Shrimati Jayanthi Natarajan) in the Chair]

Madam, I would like to say that primary education is one sector which is being totally neglected. If one goes to the gardens one will find that the children of workers are either illiterate or semiliterate, not to speak of higher education. Of course, those who have the chance to go out and have higher education have always shone in the society, they have always been able ot compete. But the chance or opportunity is very less. It has always been very less. The management always considered the appointment of teachers as an unproductive expenditure.

I would like to say that instead of leaving things in the hands of the management or the employers, the administration of the schools, the primary schools, which are situated in the gardens and their inspection, etc., the full responsibility, should lie with the State Governments. It should be taken up by the State Governments. It has never been therefore. It is important, as I have said, to build up the infrastructure for education in the gardens.

Madam, there has been an amendment to the parent Act and that amendment prohibits employment of chldiren below the age of 14 years in the plantations. I would like to say that these amendments will have no meaning unless proper facilities for education are provided in the gardens, because children who don't have the chance to go out and get themselves educated will definitely have to work in the gardens. They don't have any other option. If that happens, the purpose of bringing this amendment will be frustrated.

Madam, another sector which has always been neglected in the plantations, in the gardens, is the health and sanitation sector. This fact has also been admitted by the hon. Minister in the Statement of Objectives and Reasons. Madam, Section 10 of the Plantations Labour Act, says:

> "In every plantation there shall be provided and maintained so as to be readily available such medical facilities for the workers and their families as may be prescribed by the State Government."

This Section has been amended. The amended portion says:

> "In every plantation, there shall be—
>
> (i) established a garden hospital within two years and a group Hospital within three years of the registration of that plantation with such facilities;"

Earlier this time-frame was not there. It has been incorporated in the amendment.

What do we mean by a 'group hospital'? A 'group hospital' is a hospital among a number of gardens. The primary hospitals which are situated in the gardens have very little medical facilities to offer to the labourers or their family members. So a 'group hospital' is a hospital which is supposed to provide better medical facilities. They are supposed to have better equipments, better physicians. But we have seen that these group hospitals have not come up and the hospitals which are there in the gardens have no facilities to offer to the people at all. So it is a good thing that time-frame has been stipulated. It is two years for a 'garden hospital' and three years for a 'group hospital'. But the Government will have to see that this time-frame is strictly implemented. Madam, the penal provisions have been amended here. Sections 33, 34, 35 and 36 have been amended. The quantum of imprisonment has been raised. The quantum of fine has been raised. It is a good thing. But unless these penal provisions are implemented, the employers and the proprietors will always continue to go scot-free and the interest of the workers will continue to suffer.

Madam, before I conclude I would only like to say that the plantation industry is an industry with a colonial background. So the management of these gardens, the employers of these gardens still have that colonial mentality. They have an eye on profits. They have an eye more on profits than on the welfare of the workers. As a result the working-class has always been given a very, very low profile. Their welfare, I should say, has always received the lowest priority. This has happened after they have contributed so much to the nation's revenue, so much to the nation's economy. May I say that the employers, the owners, the management have always failed in their social obligations. This has to be enforced. This has to be made mandatory. It is the duty of the Government to see that. The Government of India, the Central Government cannot merely leave matters to the State Governments. I have already said that the State Governments have failed in their duty and the management is having a field-day at the cost of

[Shri David Ledger]

the welfare of the workers. So the Government should see that the situation is reversed and the labour class is given a fair deal. I would also like to urge upon the Commerce Ministry to draw a comprehensive scheme for the welfare of the workers.

May I sound a note of caution to the Govenment that the working class in the gardens is an exploited community. There is a growing awareness among them that they are being exploited that they are being. Unless this growing awareness is not shown due respect, unless this awareness is not taken seriously there is a possibility of social explosion, there is a possibility of more social strains and tensions in the gardens of this country. Madam, both the Ministers come from an area where there are plenty of gardens ont only tea gardens but coffee gardens also. They are well acquainted with the plight of the workers. I sincerely hope that they will do their best to improve the situation in the gardens. I also hope that the amendments to the Plantations Labour Act, 1951 will go a long way in ameliorating the socio-economic lives of the downtrodden labour class of this country.

*SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN (Tamil Nadu): Madam Vice-Chairperson, I rise to support the Planations Labour Bill on behalf of my party. I also congratulate the Hon'ble Minister for bringing this Bill to improve the living conditions of plantation labourers. The Hon'ble Members who preceded me generally held the opinion that this Bill will remove the lacunae in the original Act and will bring some substantial benefits to the workers. However, I feel that a very important aspect has been left out. Insurance coverage is something very important to the plantation workers. But unfortunately their is no reference to this aspect in the Bill. So, I request the Hon'ble Minister to make some provisions for providing insurance coverage to the workers. Whether they are plantation workers or contract workers, insurance coverage should be provided to them.

There are many welcome features in this Bill. I am happy that keeping in view the health of the workers and their families there is a provision binding on the employers to construct two types of hospitals, garden hospitals and group hospitals. I wish ot reiterate a point made by Shri Narayanasamy and some other Hon'ble Members regarding implementation of the Act. Unless the Act is implemented in letter and spirit, these amendments would prove futile. Dwelling units is a basic necessity for the labourers. When we, in the Petitions Committee, visited different plantations, we observed with pain that the workers had no proper place to live. It was a pathetic plight. But I do not find any reference to providing them dwelling units in the Bill. I hope the Hon'ble Minister will have it in mind and do the needful. It should be incumbent on the employer to provide housing facilities to all the workers.

Madam, I have a pertinent point to make. Most of the labourers are not registered by the plantation owners in order to exploit them. Employers label most of the workers as 'Casual Labourer' to deny them the benefits of this Act. If we go to a plantation we will be told that there are only 10 labourers. But in actuality there will be about 50 more labourers under the category of 'Casual Labour'. Even the so called casual labourers are working there for years regularly. The only reason to term them so, is to deny their rue and exploit them to the extent possible. I don't find any provision in the Bill to safeguard their interest. The Hon'ble Minister should do his best to put and end to this kind of exploitation. *(Time bell* Just one more minute, Madam.

I wish there was a provision in this Bill to give compensation in case of death of workers. I feel, the family of the deceased should be given atleast Rs. 25,000 as compensation. Because, they are exposed to insecticides and chemicals they fall sick very often resulting in premature death. They are also bitten by

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

poisonous creatures like snakes and scorpions in the gardens where they have to work. Therefore, employer should pay an amount not less than Rs. 25000 in the event of death of a worker. here is another welcome feature in the Bill providing punishment in case of non-implementation of the Act. If the implementation has to be fest and total it is necessary to monitor the implementaton in various states. Even central teams can be sent to different regions to monitor the implementation of the Act. I once again congratulate the Hon'ble Labour Minister for bringing this Bill,

Thank you.

*SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu): Madam, Vice Chairperson, the Hon'ble Labour Minister should visit different plantations in different regions to make a study of the problems faced by the workers. This will help in implementing this Act speedily. Even the Chief Minister of Tamilnadu very often goes Ooty to visit tea gardens there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No, No. I am calling the next speaker.

SHRI MISA R. GANESAN: Madam, I am not attributing motives. She might be really interested in the welfare of the labourers there. Our Hon'ble Labour Minister should also visit tea gardens like that to understand their problems. That is all I want to say.

श्री चतुरानन मिश्र : महोदया, यह जो प्लांटेशन लेबर अमेंडमेंट बिल है उसका तो सीमित लक्ष्य है। इसलिये उस पर आने के पहले मैं एक बात की चर्चा करना चाहूंगा कि हम लोगों ने यह योजना बनाई है कि इस शताब्दी के अन्त तक 1000 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करे। इसका मतलब यह है कि काफी विकास इसका होगा। हमारे देश में चाय की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। प्रत्येक साल करीब 4.8 परसेंट की दर से इसकी खपत बढ़ रही है। इसलिये इसके विकास की संभावना ज्यादा है। इसको देखते हुये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहां के मजदूरों की तनख्वाह का मामला जो है वह तो लड़ाई ट्रेड यूनियन वाले भी लड़ते हैं लेकिन उनके मकान, हाईजीन, उनके बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन या जो दूसरे तरह की चीजें ये हैं बड़ी नेगलेक्टेड हैं। ट्रेड यूनियन भी इसकी तरफ जोर हमारे देश में नहीं दे सके हैं : इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कुछ सोशियल जिम्मेदारी भी कम्पनियों की होनी चाहिये जो इतना प्रोफिट कमाते हैं। इसको देखते हुये एक ट्रिपारटाइट इंक्वायरी कमेटी प्लानटेशन लेबर के लिये फिर से बनाई जाय। जब हम आजाद हुये थे तो तुरन्त ऐसा किया गया था और उससे कुछ राहत मिली थी। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक दूसरी ऐसी कमेटी बने जो इन बातों की जांच करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अब तो प्लानटेशन में मोडरनाइजेशन हो गया है और नये तरीकों से बागानों में खेती हो रही है। इसमें कहा गया है कि इंसेक्टिसाइड और कैमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके चलते क्या बीमारियां मजदूरों को हो रही है, इसके लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम इसकी जांच करे। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेरा ऐसा ख्याल है कि इन चीजों के हेंडलिंग से मजदूरों को बीमारियां हो रही हैं। इसलिये अगर इसका कोई निर्णय हो जाय तो उससे इंडस्ट्रियल डिजीज के तौर पर मजदूरों को कम्पेंसेशन दिया जा सकेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करवा दी जाय तो उनको आसानी से क्षतिपूर्ति भी मिल जायेगी। ये दो कमेटियां जांच करने के लिये अवश्य बनाई जायें।

जहां तक इस बिल के प्रावधानों का संबंध है उसके संबंध में मैं दो चार बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि वर्कमैन की आपने जो परिभाषा की है उसमें कहा है कि 1600 रु0 तनख्वाह होगी। यह तो आज कल बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय

*English translation of the original points made in Tamil.

[श्री चतुरानन मिश्र]

से कहूंगा कि इसको कम से कम दो हजार और ढाई हजार तक किया जाय ताकि उनको लाभ मिल सके। जिस ढंग से यह चल रहा है उसमें उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह आप रूल्स के अन्दर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने गार्डन हास्पिटल और ग्रुप हास्पिटल की चर्चा की है, लेकिन ये कितने बेड्स के होंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा है। इसलिये रूल्स के अन्दर इसका प्रावधान कर दीजिये कि इतने मजदूर जहां पर होंगे वहां पर मिनिमिम नम्बर आफ बेड्स इतने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हास्पिटल मकान बनकर रह जायेगा।

जहां तक कम्पेंसेशन का सवाल है, इसके बारे में आपने कहा है कि मजदूर और मालिक मिलकर कोई सेटलमेंट करेंगे और कमिश्नर के यहां रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं कहता हूं कि इसको आप छोड़ दीजिये। मालिक लोग दबाव में सेटलमेंट कर लेते हैं। हम मजदूरों का आंदोलन चलाने वालों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है। एक ही प्रोविजन आप रखिये कि कमिश्नर के यहां सेटलमेंट करेंगे। प्राइवेट लोग दवाब में आकर लिखवा लेते हैं। बाद में इसमें बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है कि काम के घंटों के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि इतने ज्यादा घंटे रखे गये हैं। ऐसा लगता है कि दोनों माननीय मंत्री आसाम से आते हैं, इसलिये काम के घंटे बढ़ाकर रख दिये हैं और काम के घंटे 10 रखे गये हैं। ऐसा लगता है कि दोनों मिनिस्टरों ने अपनी तरफ से एक एक घंटा ले लिया है इसके साथ ही एक बात यह भी कही गई है कि इंस्पेक्टर की अनुमति होगी तो 12 घंटे भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। यह क्या तरीका है? यह स्पष्ट किया जाना चाहिये। सारी दुनिया में 8 घंटे काम के होते हैं। 8 घंटे काम के होने से दुनिया ढह नहीं गई है, भारत धंस नहीं रहा है और बागान भी धंस नहीं जायेंगे। इसलिये इसको स्पष्ट किया जाय।

एक निवेदन मुझे और करना है। सजा आपने बढ़ा दी है, अच्छा काम किया है और जुर्माने का क्लाज भी दे दिया है। ये लोग जेल से बचने के लिये इसका उपयोग करेंगे और जुर्माना देकर जेल से बच जायेंगे। इसलिये वहां पर जो आपने "आर" शब्द रखा है उसे काट दीजिये और अंग्रेजी के के "आर" शब्द के बजाय हिन्दी का और" शब्द रख दीजिये। इससे उनको जल और जुर्माना दोनों हो जाएगा। इसलिए आप अंग्रजी के "आर" के बजाय हिन्दी का "और' इसको कर दीजिए। जो लोग या कम्पनियां ला का उल्लंघन करती हैं उनके लिए आप प्राविजन रखिये जिसमें उनको जेल की सजा निश्चित रूप से होनी चाहिए। वैसे जेल और मुकदमों की जो व्यवस्था है वह एक अलग बात है। संक्षेप में यही मैं कहना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदया इन पर ध्यान देंगे। यद्यपि मैं इस बात से किफ हूं कि इन्टरनेशनल प्राइसेज रबड़ काफी और टी की घटी हैं और यह पिछले एक दो वर्षों के अन्दर हुआ है। सोवियत संघ के टूट जाने के बाद हमारे निर्यात व्यापार को भारी धक्का लगा है मैं इससे अवगत हूं। लेकिन अपने देश में जो खपत बढ़ रही है इसको देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन्क्वायरी कमेटी की बात जो हमने कही इसको जरूर बैठाइये और यथार्थ में इनको कुछ सहायता पहुंचाये इनको मदद पहुंचाये। क्योंकि इनका भविष्य इसके एक्सपेंशन इसके विकास में है इसका ख्याल रखते हुए इसको किया जाय। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : मैडम वाइस चेयरमैन मैं प्लांटेशन लेबर अमेंडमेंट बिल 1992 को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैडम यह जो बिल है प्लांटेशन अमैंडमेंट बिल, 1992, यह 1954 में बनाया गया था। मगर इंतिहाई अफसोस की बात है कि कभी भी इस बिल को आज तक खुली नीयत

के साथ किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। हमारे मुल्क में कई टी प्लांटेशन गार्डन हैं काफी प्लांटेशन गार्डन हैं, रबर के गार्डन हैं, टुबैको के हैं, इनमें लाखों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। सिर्फ टी प्लांटेशन में, चाय बागानों में ही लाख मजदूर काम करते हैं। मगर इसके बावजूद वहां जो मजदूर काम करते हैं उनको किसी किस्म की सहूलियत नहीं है। इम्पलायर यह चाहते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में क्राप हासिल करें और क्राप हासिल करने के लिए वे फर्टिलाइज़र और पेस्टीसाइड वगैरह का काफी इस्तेमाल करते हैं। पेस्टीसाइट सेहत के लिए इंतिहाई खतरनाक चीज होती है। जब उस प्लांट पर इस्तेमाल किया जाता है, मजदूर बिचारे निहत्ते जो होते हैं, जो उनके उसूलों से वाकिफ नहीं होते वे पेस्टीसाइड को लेकर प्लांट पर मारते हैं, छिड़कते हैं। अगर जरा सा भी पेस्टीसाइड गलत इस्तेमाल की वजह से उनकी सांस में चला जाय तो उनकी जिंदगी को काफी खतरा होता है। इनके असरात या तो फौरी होते हैं या चंद महीनों और चंद सालों के बाद भी इसके असरात होते हैं। तो इस सूरत में यह जरूरी है कि उनके ताहफुज के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ कानून होना चाहिए, कोई लेजिस्लेशन होना चाहिए। चुनाचे इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया यह बिल लाई है। मैं इसका वेलकम करता हूं।

दूसरी बात यह है कि जितने भी मजदूर हैं, जो काफी, टी, रबर और तम्बाकू के बागानों में काम करते हैं उनके लिए ग्रुप एश्योरेंस की कोई स्कीम नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि उनके लिये ग्रुप एश्योरेंस की स्कीम लागू की जाय। मैडम, उनके लिये हाउसिंग की प्राबलम भी एक बड़ा मसला बनी हुई है। उनको हाउसिंग की सहूलियत दी जाय और उनके बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज की भी सुविधा दी जानी चाहिए। वहां पर दवाखाने खोले जाने चाहिएं और बेहतर से बेहतर उनके बच्चों के इलाज का इंतजाम करना चाहिए। वहां पर उनके बच्चों के लिए किसी किस्म की एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ ही मजदूरों के लिए मोबाइल क्रेचेज होने चाहिए ताकि वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को काम पर जाने से पहले उन मोबाइल क्रेचेज में छोड़ सकें और उसके बाद काम पर जायें और अगर वक्तन-फवक्तन जरूरत हो वे बच्चों के पास आ सकें और उनकी देखभाल कर सकें और अपना काम भी कर सकें। इससे बच्चों के नसोनुमा में बड़ी मदद मिलेगी। फिर वहां पर जो लेडीज़ वरकर्स हैं उनके लिये आई.सी.डी.एस की स्कीम होनी चाहिए। उनके लिये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट स्कीम जरूर होनी चाहिए। फिर, अगर काम पर उनकी डेथ हो जाय तो डेथ कम्पन्सेशन का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। उनको डेथ कम्पनसेशन भी दिया जाय।

मैडम यह बिल एक अच्छे मकसद के लिए लाया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं और मिनिस्टर साहब से यह चाहूंगा कि हमारी तरफ से जो सजेशंस दिये गये हैं उसे ताल्लुक से वे अपने रिप्लाई में हमको जरूर एश्योरेंस दें। शुक्रिया।

سا بھی پیسٹی سائیڈ غلط استعمال کی وجہ سے ان کی سانس میں چلا جائے۔ تو انکی زندگی کو کافی خطرہ ہوتا ہے انکے اثرات یا تو فوری ہوتے ہیں یا چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد بھی اسکے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ انکے تحفظ کے لیے انکے پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ قانون ہونا چاہیے۔ کوئی لیجسلیشن ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا یہ بل لائی ہے۔ میں اس کا وہ کم کرتا ہوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مزدور ہیں۔ جو کافی۔ ٹی۔ ربر اور ٹوبیکو کے باگانوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے گروپ انشورنس کی کوئی اسکیم نہیں ہے میں یہ چاہوں گا انکے لیے گروپ انشورنس کی اسکیم لاگو کی جائے۔ میڈم انکے لیے ہاؤسنگ کی پرابلم بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ انکو ہاؤسنگ کی سہولیت دی جائے اور انکے بچوں کے لیے میڈیکل فیسلیٹیز کی بھی سوید ھا دی جانی چاہیے۔ وہاں پر دواخانے کھولے جانے چاہیں اور بہتر سے بہتر انکے بچوں کے علاج کا انتظام کرنا چاہیے وہاں پر انکے بچوں کے لیے کسی قسم کی ایجوکیشن کی فیسلیٹی نہیں ہے۔ انکے بچوں کے لیے ایجوکیشن کی فیسلیٹی ہونی چاہیے۔ اسکے ساتھ ہی مزدوروں کے لیے

شری محمد خلیل الرحمٰن "آندھرا پردیش": میڈم وائس چیرمین۔ میں پلانٹیشن لیبر امنڈمنٹ بل ۱۹۹۲ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میڈم۔ یہ جو بل ہے پلانٹیشن امنڈمنٹ بل ۱۹۹۲ یہ ۱۹۵۴ میں لایا گیا تھا مگر انتہائی افسوس کی بات کہ کبھی بھی اس بل کو آج تک کھلی نیت کے ساتھ کسی اسٹیٹ گورنمنٹ نے لاگو نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں کئی ٹی پلانٹیشن گارڈن ہیں۔ کافی پلانٹیشن گارڈن ہے۔ ربر کے گارڈن ہیں۔ ٹوبیکو کے ہیں۔ ان میں لاکھوں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں۔ صرف ٹی پلانٹیشن میں۔ چائے کے باگانوں میں ہی ۸ لاکھ مزدور کام کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہاں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی سہولیت نہیں ہے۔ ایمپلائر یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کراپ حاصل کریں۔ اور کراپ حاصل کرنے کے لیے وہ فرٹیلائزر اور پیسٹی سائیڈز وغیرہ کا کافی استعمال کرتے ہیں۔ پیسٹی سائیڈ صحت کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جب اسکو پلانٹ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزدور بیچارے ننھے ننھے ہوتے ہیں۔ جو انکے اصولوں سے واقف نہیں ہوتے وہ پیسٹی سائیڈ کو لیکر پلانٹ پر مارتے ہیں۔ چھڑکتے ہیں۔ اگر ذرا

موبائیل کوچیز ہونے چاہئیں۔ تاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پر جانے سے پہلے ان موبائیل کوچیز میں چھوڑ سکیں اور اس کے بعد کام پر جائیں اور اگر وقتاً فوقتاً ضرورت ہو وہ بچوں کے پاس آ سکیں اور ان کی دیکھ بھال کر سکیں اور اپنا کام بھی کر سکیں۔ اس سے بچوں کے نشوونما میں بڑی مدد ملے گی۔ پھر وہاں پر جو لیڈیز ورکرس ہیں انکے لیے آئی۔ سی۔ ڈی۔ ایس۔ کی اسکیم ہونی چاہیے ان کے لیے انٹگریٹیڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اسکیم ضرور ہونی چاہیے۔ پھر اگر کام پر انکی ڈیتھ ہو جائے تو ڈیتھ کمپنسیشن کا اس میں کوئی پروویژن نہیں ہے۔ انکو ڈیتھ کمپنسیشن بھی دیا جائے۔

میڈم۔ یہ بل ایک اچھے مقصد کیلئے لایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اس بل کا سپورٹ کرتا ہوں اور منسٹر صاحب سے یہ چاہوں گا کہ ہماری طرف سے جو سجیشنس دیئے گئے ہیں۔ اس کے تعلق سے وہ اپنے ریپلائی میں ہم کو ضرور انشورنس دیں۔ شکریہ

"ختم شد"

5.00 PM

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): This is the last speaker. I would like to take the sense of the House. Mr. Minister, how long will you take for your reply?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): About 10 to 15 minutes.

[Transliteration in Arabic Script]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am just taking the sense of the House. It is only the reply which is left. We can either complete it and take up the clarifications or we will put the reply off and take up the clarifications.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): We should take up the clarifications because there are clarifications on two statements.

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Only reply is there. Let it be over.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Whatever the House wants... (*Interruptions*) Yes, Mr. Minister.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam Vice-Chairman, I am grateful to all those hon. Members who have taken part in the discussion and given various suggestions about the improvement of working and living conditions of tea garden workers.

Madam, this is an Amendment with a limited purpose. We have a full Plantations Labour Act, enacted way back in 1951, and that Act came into force in 1954. And the last Amendment to this Act was in 1981. When the Government of India called the Industrial Committee on Plantations to review about the implementation of the Plantations Labour Act, in that Industrial Committee, all the employers' organisations functioning in the plantation areas and almost all the national trade unions functioning in the plantation areas were represented. They had seriously discussed about the implementation of the Plantations Labour Act, and in their wisdom, they had formed a Subcommittee to go into the details about the implementation part of the Plantations Labour Act. And they have come with some conclusions, and these Amendments are basically based on those conclusions arrived at by the tripartite Sub-committee of the Industrial Committee on the Plantations.

Madam, many hon. Members have expressed their concern about the working

[Shri Paban Singh Ghatowar]

and living conditions of the tea garden workers. Specially, Smt. Kamla Sinhaji and many other hon. Members expressed their concern about the plight of the working class in the plantation areas. It is true that tht plantation industry basically was a colonial industry. It was established by the colonial masters 200 years back, and the life in the plantation industry was really very bad. But, after the enactment of the Plantations Labour Act, there was a sea-change in the living and working conditions of the plantation workers in Assam and elsewhere. Under enactment this Plantations Labour Act, the Government has made provisions about their working conditions, working hours, medical facilities, housing facilities and others. And the implementation part of this Act has been entirely the responsibility of the State Governments.

Madam, some hon. Members expressed their concern about the housing conditions. It is true that the housing facility in the plantation area is not cent per cent. It is something like 60 per cent Hon. Member, Mr. David Ledger has mentioned that it is about 60 per cent. Still, many of the provisions of the plantations Labour Act are not properly implemented. For that reason only we have brought this Amendment with deterrent measures, increasing the punishment and fine in regard to those defaulting employers who are not implementing the provisions of the Act. There is a whole chapter in the Plantation Labour Act under which the State Government will have an Inspectorate headed by the Chief Inspector of Plantations assisted by Regional Inspectors and Labour Inspectors to see to the implementation of this Act. I think the State Governments are also trying their best to implement this Act. Whatever ills we find in this industry have been inherited from the earlier days and is not a one-day affair to fully set right everything just by passing this legislation. I think the State Governments are seriously taking interest in the improvement of the working and living conditions of the tea garden workers.

I can't say much about South India, but I can say about northern parts of India and specially the North-East, Assam and Bangal and even in the case of Bangladesh—because those days it used to be a part if India—all the working population in the plantation industry migrated from the Central Province of India, that is, part of Madhya Pradesh, part of Andhra Pradesh, part of Orissa and Chota Nagpur region, because the local people were not interested to work in the plantations. The British planters took that work force to those parts. But those workers have by now become a part and parcel of the people of those regions. Plantation workers in Assam are a part and parcel of Assamese population. So is the case with other regions. These plantation workers are taking part in all the activities there. Many of them are the elected representatives of the people in Assam and other regions. They do not represent plantation workers or the tea garden community. They represent the people of that State. My own forefathers migrated to Assam about 150 years ago from the Central Province and they used to work in plantations. Of course, later on we shifted to cultivation. So it will not be correct to say that these people are isolated. Yes, they are isolated in the sense that they live in a colony in an isolated remote place where they face many problems, social problems and others. They do not have better education facilities for their children. One hon. Member said about education. There is a clear provision for education in the Act. It is the responsibility of the management under the Act that where the number of children is more than 25 in any plantation, the management is bound to provide a primary school for the education of the children of tea garden workers.

Previously the dependent of a male worker only was treated as dependent to claim all the facilities like concessional food stuff and medical facilities etc. With this amendment, because more than 45 per cent of workers in plantations are women, we have provided that dependent

of a woman worker also will be entitled to those benefits. Shri Jagesh Desai from the Chair asked about plantation industry in the public sector and what happens if the public sector employer violates the Act. Previously there was no provision in the Act but now we have included Government officials also under the employer category and they are treated equally as private employer under the Act. Madam, a lot of concern has been expressed by hon. Members on the use of pesticides and weedicides in the plantations. Tea is basically an agro-based industry. It is a very popular drink all over the world. The people to whom we sell our tea must be naturally concerned with their health. Sixty per cent of the Assam tea is sold in Europe. The people there would be concerned about their health and they would not be very much interested in taking something which is injurious to their health. I think the chemicals that we use in our tea plantations are generally not of a poisonius type. These are mostly pesticides and weedicides. There is an agency which certifies the chemicals used. There is a scientific...

SHRI S. S. AHLUWALIA: I was not talking about that. I was not saying that the tea is poisoned. I was talking about the workers, the labourers, who spray these pesticides and insecticides. These workers may be affected. Not the tea. Those who do the spraying would be affected. I was asking about that.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: That is the reason why we have brought forward this amendment. In this, we have given some safety protection. It provides for giving protective clothing and protective implements to the workers so that when they are handling these chemicals, they will use these protective implements.

SHRI V. NARAYANASAMY: What about compensation?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: There are inspectors to look after these things. In regard to medical facilities, the State Governments have appointed Inspectors who go to the plantations and check as to what type of medical facilities have been provided in these plantations. There are Labour Inspectors, there are Plantation Inspectors, appointed by the State Governments. They go to the plantations and see whether the provisions of the Act are being implemented. Of course, I must admit that everything is not well in the plantations. That is the reason why the Government of India decided to bring forward this amendment.

Madam, with these words, I would humbly request all hon. Members to support this amendment so that the plantation workers all over the country can get the benefits of this legislation. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The hon. Minister has answered all the questions.

SHRI S. S. AHLUWALIA: What about the compensation?

SHRI V. NARAYANASAMY: What about the compensation part? There is nothing in this Bill.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is still talking about the Workmen's Compensation Act. Why not a separate provisions here in regard to compensation? He should assure the House that he would bring forward legislation in this regard.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I just want to point out one thing. I do not want to allow any further questions. I would request hon. Members to co-operate because we have the clarifications on the two statements made yesterday and then we have the Half-an-hour Discussion.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He should assure us.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He is replying to it, but I wanted to say this in order to stop further questions.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: What about group insurance?

[Shri Tindivanam G. Venkataraman]

Is the Government thinking of introducing a Group Insurance Scheme for the workers?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam, as of now, the plantation workers are covered by the Workmen's Compensation Act. They are getting all the benefits available under the Workmen's Compensation Act. The hon. Member has asked about group insurance. I think majority of the workers are members of the EPF organisations.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: I am not talking about provident fund.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: In the EPF scheme, we have the Deposit-linked Insurance Scheme.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: Provident fund is different from insurance.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: We have the Deposit-linked Insurance (DLI) Scheme. All the plantation workers are covered by it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Now the question is:

> "That the Bill further to amend the Plantations Labour Act, 1951, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 25 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

ALLOTMENT OF TIME FOR CONSIDERATION OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) AMENDMENT BILL

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I have to inform the Members that the Business Advisory Committee at its meeting held to day, 30th July, 1992, allotted 3 hours for consideration and passing of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Amendment Bill, after it is passed by the Lok Sabha.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER REGARDING ROCKET ATTACKS IN SRINAGAR AND SITUATION IN DODA TOWN

डा० बलदेव प्रकाश (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है श्रीनगर पर राकेट दागे जाने और डोडा कस्बे की स्थिति के बारे में, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने स्थिति की गंभीरता को कम करके यह वक्तव्य दिया है कि पहले से गुणात्मक परिवर्तन जम्मू और कश्मीर की स्थिति में आया है । उस परिवर्तन की मंत्री महोदय ने व्याख्या नहीं की, केवल इतना ही कहा है कि प्रशासन और जनता में आपस में इंटरएक्शन संभव हो सका है और कुछ सूचना वगैरह अधिक मिली है । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि डोडा जिले में चिंदा और चांदा, दो स्थान हैं, जहां पर आज भी आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैम्प चल रहे है ? डोडा जिले में एक हजार से अधिक ट्रेण्ड आतंकवादी इस वक्त वहां मौजूद हैं और इसके अलावा जो बाकी आबादी है वह उनके साथ संपर्क रखती है और उनको गोला-बारूद और हथियार पहुंचाने के लिये लगे रहते हैं, यह डोडा की घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । उसी रास्ते से यह सभी आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जहां पर सन् 1950 में इनफिलट्रेशन हुई थी बड़ी मात्रा